31 OCT 11 2026.qxd 30-10-2026 23:06 Page 1

'हमारी राधा' ने पूरे किए 100 एपिसोड्स



अनमोल टीवी के पहले ओरिजिनल शो 'हमारी राधा' ने 100 एपिसोड्स पूरे कर लिए हैं, जो कि शो और उसकी पूरी टीम के लिए एक विशेष उपलब्धि है। इस मौके पर सेट पर जश्न मनाया गया, जहाँ पूरी टीम ने साथ मिलकर केक काटा और शो के किरदारों और उनकी कहानियों को दर्शकों तक पहुँचाने के अब तक के सफर को याद किया। सिमरन कौर, अक्षय म्हात्रे और वैदेही नायर अभिनीत 'हमारी राधा' की कहानी मुख्य रूप से राधा के जीवन पर केन्द्रित है। राधा का भरोसा तब डगमगाने लगता है, जब उसे अपने पति गिरधर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चलता है। जब राधा अपने रिश्ते में मिले धोखे और शादी में आ रहे बदलावों का सामना करती है, तो धीरे-धीरे उसे अपने हक के लिए आवाज़ उठाने की हिम्मत मिलने लगती है। इस कहानी के माध्यम से शो रिश्तों की उलझनों, पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक आकांक्षाओं के बीच के फर्क और खुद को नए सिरे से पहचानने के लिए जरुरी हिम्मत को सामने लाता है। शो का हिस्सा बनना कलाकारों के लिए सिर्फ अपने किरदारों को पर्दे पर निभाने तक ही सीमित नहीं रहा है। 'हमारी राधा' के 100 एपिसोड्स पूरे होने के इस खास मौके पर कलाकारों ने अपने इस सफर के अलग-अलग अनुभव साझा किए। इनमें एक कलाकार के तौर पर उनका व्यक्तिगत विकास और दर्शकों के बीच उनके किरदारों को मिली प्रतिक्रियाएँ भी शामिल हैं। 'हमारी राधा' के 100 एपिसोड्स पूरे होने के साथ कहानी में राधा, गिरधर और शनाया के बदलते रिश्तों का सफर आगे बढ़ रहा है, जहाँ उनके फैसले उनकी जिंदगी की दिशा तय कर रहे हैं।

डीएचएल एक्सप्रेस इंडियाने शिपमेंटपर 60प्रतिशत तक की दी त्योहारी छूट

प्रयागराज- दुनिया की अग्रणी अंतरराष्ट्रीय एक्सप्रेस सेवा प्रदाता कंपनी डीएचएल एक्सप्रेस पूरे भारत में अपने ग्राहकों के लिए विशेष त्योहारी छूट के साथ दिवाली का उत्सव मना रही है। सीमित अवधि के लिए उपलब्ध यह ऑफर 14 नवंबर 2026 तक मान्य है। इसके तहत ग्राहकों को अंतरराष्ट्रीय और घरेलू शिपमेंट पर 60प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। जो ग्राहक भारत और दुनिया भर में अपने परिवारजनों और प्रियजनों को उपहार, मिठाइयाँ और त्योहार की शुभकामनाएँ भेजना चाहते हैं, वे डीएचएल की वेबसाइट पर या डीएचएल सर्विस पॉइंट पर प्रोमोशन कोड FESTIVAL60 का उपयोग कर सकते हैं।ग्राहक डीएचएल गोग्रीन प्लस सेवा का विकल्प भी चुन सकते हैं।

यूपीमें हो रही बारिशसे प्रभावितोंको तत्काल राहत देने का मुख्यमंत्री योगी का निर्देश

लखनऊ (हि.स.)। उत्तर प्रदेश में हो रही बारिश को लेकर सरकार सतर्क है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारिश से प्रभावितों को तत्काल राहत देने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने शुक्रवार को जारी निर्देश में कहा कि अतिवृष्टि से हुई, आर्थिक हानि, पशुहानि पर तत्काल मुआवजा दिया जाए। बारिश में जिनके घर गिरे, उन्हें तत्काल अनुमन्य मुआवजा उपलब्ध कराएं। फसल बर्बादी का तत्काल आकलन कर किसानों को यथाशीघ्र मुआवजा दें। यह भी ध्यान रखा जाए कि घर गिरने से बेघर हुए लोगों को तत्काल राहत केंद्र और शरणालय केंद्र पहुंचाएं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी फील्ड में रहकर प्रभावित परिवारों से संवाद करें। प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता तत्काल उपलब्ध कराएं। राहत कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उल्लेखनीय है कि गुरुवार की शाम से ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम खराब है। कहीं तेज बारिश हो रही है तो कहीं लगातार बूंदा-बांदी हो रही है।



गोरखपुर को योगी कल देंगे 1663 करोड़ की सौगात

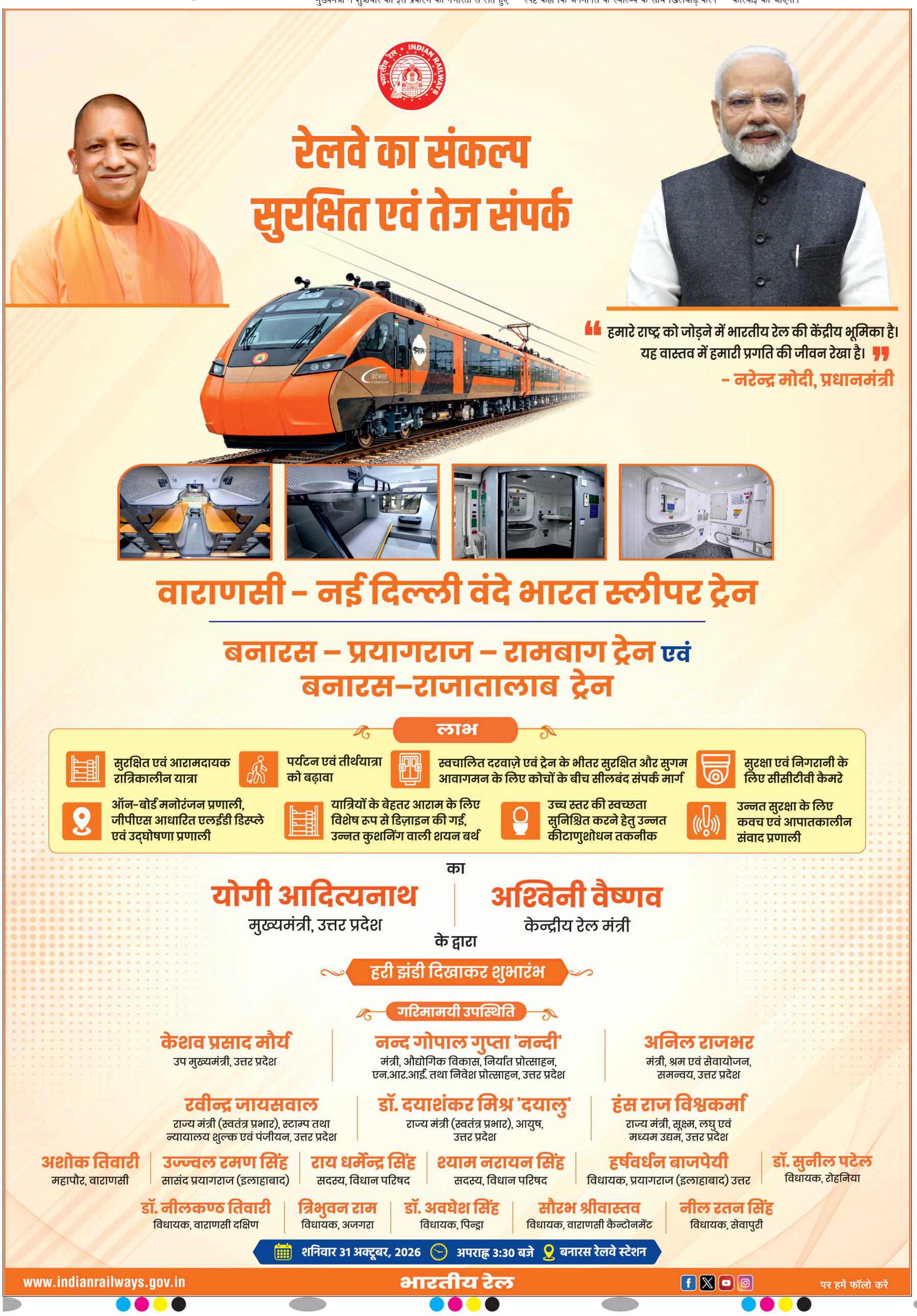
गोरखपुर (हि.स.)। गोरखपुर की बदलती तस्वीर और आधुनिक बुनियादी ढांचे के संकल्प को गति देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपावली से एक सप्ताह पहले ही, एक नवंबर को जिले को करीब 1663 करोड़ रुपये की लागत वाली 88 विकास परियोजनाओं का दीपावली उपहार देने जा रहे हैं। इन परियोजनाओं में रोड कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, नगरीय जीवन सुगमता, बाढ़ से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। सीएम योगी, चौरीचौरा क्षेत्र को जाम से मुक्ति दिलाने वाले महत्वपूर्ण रेल ओवरब्रिज का लोकार्पण करने के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, बाढ़ बचाव, गोरखपुर शहर के जलभराव और सीवर प्रबंधन से संबंधित गोड़धोइया नाला परियोजना फेज एक का लोकार्पण और परियोजना के फेज दो, नाले के समानांतर सड़क और गोरखपुर सीवरेज योजना जोन ए 3 का शिलान्यास करेंगे।

छह राज्यों और दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण की समयसीमा बढ़ी

नयी दिल्ली (आससे.)। भारत निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, नगालैंड और दिल्ली में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्यक्रम बढ़ा दिया है। आयोग के अनुसार, महाराष्ट्र में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 13 नवंबर कर दी गई है। यहां इनके निस्तारण की प्रक्रिया 25 नवंबर तक चलेगी। नगालैंड में भी दावे-आपत्तियों के निस्तारण की अवधि 25 नवंबर तक रहेगी। आंध्र प्रदेश और हरियाणा में यह प्रक्रिया 20 नवंबर तथा तेलंगाना में 26 नवंबर तक चलेगी। इन पांच राज्यों में अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर को प्रकाशित होगी। वहीं, दिल्ली में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 25 नवंबर कर दी गई है।

सील अस्पतालों को नये नाम से चलाने और अवैध वसूली के मामले में सरकार सख्त

लखनऊ (आससे.)। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उन वीडियो और खबरों का गंभीरता से संज्ञान लिया है जिनमें लखनऊ, कानपुर और उन्नाव में पूर्व में सील किए गए अस्पतालों को नए नाम से संचालित किए जाने और मरीजों से अवैध वसूली किए जाने के आरोप सामने आए हैं। उप मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं कि स्वास्थ्य महानिदेशालय स्तर से तीन सदस्यीय जांच टीम गठित कर पूरे मामले की गहन जांच कराई जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि जांच आख्या के साथ-साथ दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई का प्रस्ताव एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराया जाए। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जनमानस के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने तथा विभाग एवं सरकार की छवि धूमिल करने वाले मानकविहीन और सील किए गए चिकित्सालयों का अवैधानिक संचालन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सील अस्पतालों को नए नाम से संचालित करने, मरीजों से अवैध वसूली करने तथा इस पूरे प्रकरण में संलिप्त पाए जाने वाले लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।



पृष्ठ एक और तीन का शेष

यूपीमें दीपावली...

बसों की मरम्मत और जरूरी कलपुर्जों की उपलब्धता पहले से सुनिश्चित करने को कहा गया है। त्योहार के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष परिस्थितियों को छोड़कर छुट्टी नहीं दी जाएगी। बस अड्डों पर साफ-सफाई, पीने के पानी, बैठने, डिजिटल समय सारिणी और सहायता केंद्र की व्यवस्था भी की जाएगी। परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि 11 दिन ड्यूटी करने वाले चालकों और परिचालकों को 4400 रुपये तथा 12 दिन ड्यूटी करने पर 4800 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए प्रतिदिन औसतन 300 किलोमीटर बस चलाना अनिवार्य होगा। संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को निर्धारित दूरी से अधिक संचालन पर 55 पैसे प्रति अतिरिक्त किलोमीटर भी मिलेंगे। इलेक्ट्रिक बसों पर 11 दिन में 3300 किलोमीटर संचालन करने वाले चालकों को करीब एक हजार रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। कार्यशाला के कर्मचारियों को भी 11 दिन ड्यूटी पर 2100 और 12 दिन ड्यूटी पर 2500 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। परिवहन निगम दिल्ली से लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या और कानपुर के लिए अतिरिक्त बसें चलाएगा। इसके अलावा गाजियाबाद, मुरादाबाद, मेरठ, बरेली, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़ और इटावा के लिए भी बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। चालकों और परिचालकों की ब्रेथ एनालाइजर से जांच होगी, ताकि नशे की हालत में कोई चालक बस न चलाए।

दिल्लीमें होने...

तेलंगाना और पंजाब सहित विभिन्न राज्यों से आने वाले लोगों को गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसके बावजूद रैली में शामिल होने वाले लोगों की तादाद से देशवासियों में व्याप्त भारी आक्रोश का पता चलेगा। राहुल गांधी ने कहा कि देश में बहुत ज्यादा गुस्सा और गहरा भावनात्मक दर्द है, क्योंकि लाखों लोगों से वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उद्योगपति अडानी व अंबानी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के लाभ के लिए जनता के वोट चुराए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष का यह आंदोलन अलग-अलग विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक साझा लड़ाई है। पूरा विपक्ष एकजुट होकर संविधान, भारत के विचार और प्रत्येक नागरिक के वोट की रक्षा कर रहा है, जो सभी भारतीयों की अभिव्यक्ति है। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि राहुल गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और पूरा विपक्ष लोकतंत्र तथा संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ रहा है। अब देश के लोगों को भी यह अहसास होने लगा है कि भाजपा की मदद के लिए ईवीएम से लेकर मतदाता सूचियों तक, हर चीज में हेरफेर की गई है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के एमएलसी चुनावों में वाराणसी, लखनऊ, झांसी, प्रयागराज और आगरा सीटों पर भाजपा की करारी हार का उल्लेख करते हुए कहा कि इन परिणामों से विपक्ष को एक नई ऊर्जा मिली है। उन्होंने कहा कि जहां पर भाजपा ने जीत दर्ज भी की है, वहां बेईमानी से कुछ मतों के अंतर से जीत हासिल की है। वहीं, तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी दल इस लड़ाई में एक साथ हैं। उन्होंने कहा कि सिविल सोसायटी, छात्र, युवा, कामगार और महिलाएं भी इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं।

बद्रीनाथ...

हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही सेना, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एसडीआरएफ) की टीमें मौके पर पहुंच गईं। राहत एवं बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। मृतकों के शवों को दुर्गम जंगल से सड़क तक लाने की कार्रवाई की जा रही है।

वाराणसी-दिल्ली...

वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की प्रीमियम रात्रिकालीन सेवाओं की नई कड़ी है। अब तक वंदे भारत ट्रेनें मुख्य रूप से दिन में चलने वाली चेयरकार सेवाओं के रूप में संचालित होती रही हैं। स्लीपर संस्करण को लंबी दूरी की यात्रा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे यात्री रात में आराम से सफर कर सुबह अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। इस सेवा से वाराणसी के अलावा प्रयागराज और कानपुर के यात्रियों को भी दिल्ली आने-जाने का अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। धार्मिक यात्रा, कारोबार, शिक्षा, नौकरी और पर्यटन के सिलसिले में दोनों क्षेत्रों के बीच यात्रा करने वाले लोगों को इससे सुविधा होगी।

यूपीमें गुप्त...

मंत्रालय ने बताया डीआरआई को इस गुप्त ठिकाने के बारे में पुख्ता खुफिया जानकारी मिली थी। इसी आधार पर यूपी एटीएस की एक बड़ी संयुक्त टीम ने 29 को तड़के संदिग्ध ठिकाने पर अचानक छापेमारी की। मौके से टीम ने लगभग 184 किलोग्राम अर्ध-निर्मित ड्रग्स, करीब 582 किलोग्राम कच्चे रसायन और भारी मात्रा में ड्रग्स बनाने के आधुनिक उपकरण जब्त किए। आरोपियों के पास से लगभग 15.4 किलोग्राम तैयार मेथाक्वालोन, 153 किलोग्राम अन्य रसायन और ड्रग्स निर्माण में इस्तेमाल होने वाली एक मशीन बरामद की गई। इसके अलावा, एक अन्य आरोपी के ठिकाने से 168 किलोग्राम कच्चे रसायनों की एक और बड़ी खेप जब्त की गई। इस अवैध नेटवर्क से जुड़े दो प्रमुख मास्टरमाइंडों को स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के कड़े प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है।

९.३४...

एक सदस्य को प्रतिवर्ष छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता दो-दो हजार रुपये की तीन किस्तों में प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर पोस्ट कर दीपावली से पहले मिले उस उपहार के लिए उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों की तरफ से प्रधानमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने लिखा कि किसानों की खुशहाली में गांवों की समृद्धि और गांवों की समृद्धि में राष्ट्र की प्रगति निहित है। इसी संकल्प के साथ आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने गुजरात के बनासकांठा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त के अंतर्गत देश के 9.34 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,690 करोड़ रुपये से अधिक की सम्मान राशि सीधे अंतरित की। इससे उत्तर प्रदेश के 2.24 करोड़ रुपये से अधिक किसान साथी लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने लिखा कि अन्नदाता किसान बंधुओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने, उनकी आय बढ़ाने और खेती की लागत कम करने के लिए डबल इंजन सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। दीपावली से पूर्व प्राप्त इस उपहार के लिए उत्तर प्रदेश के समस्त किसान बंधुओं की ओर से आपका हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी। शुक्रवार को 4482.19 करोड़ जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में अब तक 107,943.95 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं।

सौरव दास...

जी. अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने शुक्रवार को इस जनहित याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने सौरव दास, केंद्र सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए उनका जवाब मांगा है। अदालत ने मामले को छह सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। यानी अब संबंधित पक्षों को याचिका में लगाए गए आरोपों और मांगों पर अपना पक्ष रखना होगा। यह याचिका तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले के रहने वाले गणेश कुमार ने दायर की है। इसका शीर्षक गणेश कुमार बनाम क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी है। याचिकाकर्ता ने अदालत से दास की पहचान, राष्ट्रीयता और उनके पारिवारिक इतिहास की जांच कराने की मांग की है। गणेश कुमार ने अपनी याचिका में सौरव दास की पहचान और पृष्ठभूमि की विस्तृत जांच कराने की मांग की है। इसमें उनके माता-पिता से जुड़ी जानकारी की जांच करने की बात भी कही गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि अधिकारियों को दास की नागरिकता और व्यक्तिगत पृष्ठभूमि से जुड़े तथ्यों की पड़ताल करनी चाहिए। याचिका में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को भी पक्षकार बनाया गया है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने दास के पासपोर्ट से जुड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय और अन्य संबंधित अधिकारियों से भी उनकी पृष्ठभूमि और व्यक्तिगत विवरण की जांच कराने की मांग की गई है। हालांकि, दास की राष्ट्रीयता को लेकर लगाए गए ये आरोप फिलहाल याचिका का हिस्सा हैं। अदालत ने अभी इन आरोपों पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया है।

यूपी : एसआईआर...

आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के एक विधानसभा क्षेत्र में एक खास समुदाय के लोगों के नाम मतदाता सूची से हटवाने के लिए 32 फॉर्म-7 जमा किए गए थे। उन्होंने दावा किया कि कुछ फॉर्म पर बूथ लेवल ऑफिसर के हस्ताक्षर भी मौजूद हैं।याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग के हलफनामे में दी गई जानकारी पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि आयोग की ओर से दी गई जानकारी में कई अंतर हैं, जिनकी जांच जरूरी है

चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस नायडू ने स्वीकार किया कि बड़ी संख्या में फॉर्म-7 जमा किए गए थे। हालांकि, उन्होंने अदालत को बताया कि आयोग के अधिकारियों ने इन फॉर्म की जांच की थी और उन्हें गलत पाया था। इसी वजह से इन आवेदनों के आधार पर किसी भी मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाया गया। उन्होंने कहा कि यदि किसी शिकायत में तथ्य हैं, तो संबंधित पक्ष औपचारिक शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके बाद चुनाव आयोग मामले की जांच करेगा।याचिकाकर्ताओं ने सुनवाई के दौरान तेलंगाना और कर्नाटक का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे। उनका आरोप था कि उत्तर प्रदेश में कार्रवाई नहीं होने से इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा मिला। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को लंबित शिकायतों का विवरण चुनाव आयोग को देने और आयोग को उनकी जांच कर जरूरी सुधार तथा कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने को कहा।